outside who can carry the knowledge and the results of the research to the backward areas?

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: I can appreciate his point because we have found on assessment that even when the research findings are there, we are unable to take the results to millions of farmers. Therefore, our entire emphasis is to—implement the programme of extension and see that the research results are taken to the farmers in the backward areas as well as other areas.

श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान : जनाब स्पीकर साहब, आपके जरिये मैं यह जानना चाहता हूं कि भारत में यों तो बहुत सारे बैकवर्ड इलाके हैं लेकिन उनमें नौर्थ बिहार बहुत ही पिछड़ा इलाका है। क्या सरकार एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को उन इलाकों में पोस्ट करेगी जो वहां के लोकल नीड्स को देख कर इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाये और सरकार को सुझाव दें कि वहां के किसानों को इन बातों की आवश्यकता है ताकि वहां की हालत में सुधार आये?

अध्यक्ष महोदय: Forget about it. बैकवर्ड इलाके हैं वहां भेजेंगे? इसके जवाब में मिनिस्टर साहब कह देंगे कि भेजेंगे। तो इससे आपको क्या सतोष मिलेगा।

श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान: उनसे कहिये कि आप देखें कि करोड़ो रुपया आप खर्च करते हैं इसलिये उनके बारे में कुछ तो मंत्री जी जवाब दें।

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: We do not consider North Bihar backward from this angle, because scientists go there and research stations are there. By backward areas I mean areas like Lahaul, Spiti, the hill areas of UP etc.

SHRI PARIPURNANAND PAINULI: The hill areas like Kashmir, H.P., hill districts of UP etc. have good potential for production of cash crops like fruits and vegetables. Yet, the Agriculture Ministry continues to lay emphasis on the production of foodgrains in these areas. Mr. Shinde himself paid a visit to Tehri Garhwal sometime back and he was convinced that the soil there is very much suitable for the production of cash crops. May I know whether a team of horticultural experts will be sent to these areas so that they can advise the local people to grow better fruits and better vegetables?

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE: The hon. member is not correct that we are laying emphasis on food crops only in these areas. In fact, our maximum effort is on horticulture and growing of vegetables in these areas.

मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनायें

+

*87. श्री हुकम चन्द कछवाय:
श्री गंगा चरण दीक्षित:

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पांचवीं योजना अवधि में मध्य प्रदेश में कितनी सिंचाई परियोजनाएं आरम्भ करने का विचार है; और

(ख) उनके लिये कितनी केन्द्रीय सहायता दिये जाने की संभावना है और इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री केदार नाथ सिंह): (क) मध्य प्रदेश की पांचवीं योजना के प्रस्तावों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) सिंचाई राज्य विषय है और बृहत् तथा मध्य सिंचाई स्कीमों के लिए

प्रावधान राज्य सरकारों द्वारा अपनी विकासात्मक योजनाओं में वार्षिक आधार पर किया जाता है। राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों तथा अनुदानों के रूप में दी जाती है तथा यह विकास के किसी विशिष्ट शीर्ष अथवा परियोजना से सम्बद्ध नहीं होती ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपने अभी बताया कि मध्य प्रदेश की सिंचाई योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया। इसे अन्तिम रूप देने में कितना समय लगेगा आप, और क्या योजना है? किन स्थानों पर कितने पैमाने पर कितनी सिंचाई हो सकेगी, उसके लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं? मध्य प्रदेश सरकार ने कोई आपसे सहायता मांगी है कि वह कहां कहां आपका सहयोग चाहती है? यदि हां तो किन विषयों के बारे में आपसे सहायता मांगी है?

श्री केदार नाथ सिंह : माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, तो राज्य सरकारों ने जो हमें हमारे कमीशन से किया है उस आधार पर जिलेवार आंकड़े कुछ नहीं हैं। योजना जो आती है उस आधार पर वहस होती है। पंचवर्षीय योजना में जो प्रोवीजन दिया गया है वह 200 करोड़ रु० का है जिसमें 76.83 करोड़ जो हमारी योजनायें चल रही हैं उन पर है, 115.17 करोड़ नई स्कीमों के लिये है और 8 करोड़ रु० रिसर्च और इन्वस्टीगेशन के लिये है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मध्य प्रदेश के लिये कितना आपने रखा है, उसका उत्तर नहीं आया है। सारे देश का आपने बता दिया, मध्य प्रदेश के लिये कितना है?

श्री केदार नाथ सिंह : पांचवीं पंचवर्षीय योजना में जो है, वह मैंने बताया है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : आपने प्रश्न के अन्त में बताया है कि ब्लाक या अन्य योजना के माध्यम से हम राज्य सरकार को अनुदान या दान देते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि नये प्रस्ताव में आप कितना अनुदान राज्य सरकार को दे रहे हैं और उससे कितनी योजना सफल होगी। झबुआ, धार, भिण्ड, रतलाम, बस्तर, छत्तीसगढ़, ये इलाके बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं क्योंकि उनके लिए कोई योजना नहीं है। ये पिछड़े हुए जिले हैं और इनमें सिंचाई की योजना होना अत्यावश्यक है। यहां पर काफी भूमि उपजाऊ है और इस को ध्यान में रखते हुए आपने वर्तमान समय में कितना पैसा देने का वचन दिया है और कितना आप देना चाहते हैं?

श्री केदार नाथ सिंह : जैसा कि मैंने बताया है कि सिंचाई का विषय राज्य सरकार का है और राज्य सरकार ही प्रायरिटीज तय करती है। हम तय नहीं करते हैं। राज्य सरकार ही इस बात को तय करती है कि किस योजना में कितना खर्च करना है।

श्री बरबारा सिंह : मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि जब कि मध्य प्रदेश में तकरीबन 6 परसेन्ट ही सारी सिंचाई है और वह इतना बड़ा सूबा है लेकिन जब भी इस बारे में डिस्कशन होते हैं, तो आप क्यों नहीं मध्य प्रदेश सरकार की मदद करते हैं ताकि उस को ज्यादा पैसा इसके लिए मिल जाए।

श्री केदार नाथ सिंह : यह जो सुझाव आपने दिया है इस पर राज्य सरकार ने खुद गौर किया है। वहां पर अन्तर्राज्य कुछ झगड़े हैं जो कि तय नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए यह सब बात है।

श्री राम सहाय पांडे : मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूं उसमें कष्ट तो जरूर होगा जवाब देने में। प्रश्न यह है :

what are the irrigation projects proposed to be launched in Madhya Pradesh during the Fifth Five Year Plan period? पहले तो यह बताइये कि पांचवीं प्लान आप ही बनाते हैं और आप कहते हैं कि यह स्टेट की बात है । पांचवीं प्लान में आपने किन-किन योजनाओं को मध्य प्रदेश के लिए प्रस्तावित किया है । इसके अलावा यह बात भी है कि नर्मदा का सम्बन्ध भी आपसे है और उस में कुछ गुजरात और मध्य प्रदेश का झगडा है । इसके बारे मे क्या पोजीशन है और पांचवीं पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश के लिए सिचाई के लिए क्या क्या प्रस्ताव हैं ? यह भी आप बताइए । हम जानते हैं कि आपको बताने में कष्ट तो होगा ।

श्री केदार नाथ सिंह : जो प्रस्ताव तैयार होते हैं वह राज्य सरकार तैयार करती है । हम उनको तैयार नही करते है ।

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, नर्मदा योजना जो है, यह हमारे लिए बडी महत्व की है । नर्मदा नदी हम लोगों के लिए और मध्य प्रदेश के पिछडे इलाको के लिए जीवन रेखा है । मैं केन्द्र सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि यह योजना 15 वर्ष से चल रही है और इस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है । क्या यह सही नही है कि वहा के मुख्य मंत्री श्री प्रकाश चन्द सेठी, जो केन्द्र मे मंत्री रह चुके हैं, मध्य प्रदेश के हितो का ध्यान नही रख रहे हैं और चुपचाप समझौता कर लेते हैं । इसीलिये यह योजना ठीक से नहीं चल रही है । यह योजना जल्दी जल्दी क्यों नहीं चल रही है ..... (व्यवधान) ..... हम सब आदिवासी इलाके के लोग हैं ..... (घंटी) अध्यक्ष महोदय सुनिये । यह जो नर्मदा योजना है इस पर चुपचाप श्री प्रकाश चन्द सेठी ने समझौता कर लिया है और यह इनके द्वारा थोपे हुए मंत्री है । इन्होंने चुपचाप समझौता कर लिया है । तो यह बताने की कृपा करे कि इस सवाल को सुलझाने में कितना समय लगेगा और इस योजना को जल्द से जल्द कब शुरू किया जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : आप बैठेंगे तो वह जवाब देंगे ।

श्री केदार नाथ सिंह : माननीय सदस्य को शायद मालूम है कि नर्मदा का मसला ट्रिब्यूनल के सामने सुपुर्द है और दो सरकारें उसमें शामिल हैं खास तौर से गुजरात और मध्य प्रदेश । वे सरकारें आपस में समझौता नहीं कर पा रही हैं । इसलिए देर हो रही है और मजबूरी है..... (व्यवधान)

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, जल्दी फैसला क्यो नही किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये, उन्होंने जवाब दे दिया है । यह क्वेश्चन आवर है ।

SHRI P. K DEO: From the information supplied by the Minister we learn that some of the projects are pending consideration because of the inter-State water dispute tribunal. So far as Narmada is concerned, I believe, it is felt to the Prime Minister. Why is she taking time in allocating the quantum of waters of the Narmada to Gujarat and Madhya Pradesh?

So far as other projects in Madhya Pradesh in the Godavari Basin are concerned, it is under adjudication by the Krishna Godavari Water Commission. The Commission has taken such a long time and the country is passing through food and power shortage. I would like to know the time limit by which the Krishna Godavari Water Commission is going to give its award so far as the allocation of water to the various States, including Madhya Pradesh, is concerned.

श्री केदार नाथ सिंह : इसके लिए नोटिस चाहिए क्योंकि इसमें कृष्णा गोदावरी का मामला नहीं आता है ।

SHRI P. K. DEO: Bodhghat Project in Bastor is in the Godavari basin. You should know that.

SHRI KEDAR NATH SINGH: I know. But that is before the Tribunal and no time-limit can be fixed for the Tribunal's report. They have to take their own time in giving their report.

Central Team for Drought Hit Tamil Nadu

+

*89. SHRI S. A. MURUGA NANTHAN:

SHRI R. V. SWAMINATHAN:

Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) district-wise number of people hit by recent drought in various districts of Tamil Nadu;

(b) whether any central study team toured these districts to apprise of the seriousness of the drought conditions;

(c) whether Government have noted reports of distress sale of cattle, loss of agricultural production and mass migration of farm labour from the worst-hit areas of the State; and

(d) the assistance given by the Centre and the State Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE): (a) to (d). A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) The number of people affected by drought in the various districts of Tamil Nadu is as under :—

	Rs. in lakhs
Chingleput	14·12
North Arcot	17·00
South Arcot	17·76
Thanjavur	6·61
Tiruchirapalli	15 41
Pudukkottai	11·41
Madurai	13·05
Ramanathapuram	20·23
Tirunelveli	13·55
Salem	11·88
Dharmapuri	4·79
Coimbatore	13·77

(b) Some of the districts were visited by a Central Study Team.

(c) The loss of agricultural production as a result of the drought has come to Government's notice. However, the State Government have denied Press reports of distress sale of cattle. Agricultural labourers in the worst affected districts like Pudukkottai, Ramanathapuram and Madurai, have migrated to Thanjavur district in anticpation of better employment opportunities in the harvest season. The State Government is taking all possible steps to provide employment to the agricultural labourers in their local areas by undertaking drought relief works.

(d) The Government of India have sanctioned a sum of Rs. 7.50 crores as advance plan assistance to Tamil Nadu. The State Government have also sanctioned a sum of Rs. 10 crores for undertaking relief works.

SHRI S. A. MURUGANANTHAM. The Minister's statement shows that more than 1½ crores of people out of